P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-6* ISSUE-9*(Part-1) May- 2019
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

भारत में वामपंथी अतिवाद–नक्सलवाद के विशेष संदर्भ में

ललिता दादरवाल
व्याख्याता,
राजनीति विज्ञान विभाग,
सुबोध महिला महाविद्यालय,
जयपुर, राजस्थान, भारत

सारांश

नक्सलवाद सामाजिक, आर्थिक पिछड़ेपन, गरीबी, बेकारी और भौगोलिक विषमताओं की जड़ से उत्पन्न एक सशस्त्र आंदोलन है जो सरकारी नीतियों व प्रशासन के विरुद्ध बन्दूक की गोली से गरीब भारतीय मजदूरों और किसानो की दुर्दशाओं का हल निकालना चाहते हैं जो सम्भव नहीं है यह आत्म–समर्पित माओवादियो के बयानों का फलितार्थ है। विचारों और परिस्थितियों से उपजी जंग को बुद्धिमता व धैर्य द्वारा लड़ा और जीता जाना चाहिए। सदियों से शोषक व शोषित के मध्य संघर्ष होता रहा है जिसका समाधान हिंसा नहीं बल्कि समस्या की जड़ को निर्मूल करने का दृढ़ निश्चय आवश्यक है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पूरी ईमानदारी से विकास कार्यो, शिक्षा व रोजगार की प्राथमिकता देनी होगी।

मुख्य शब्द : नक्सलवादी, वामपंथी, विस्थापन, भूमिगत, सल्वाजुडुम, सर्वहारा की क्रान्ति, माओवाद, अतिवाद, कम्युनिस्ट, प्रस्थान बिन्दु, सामन्तवाद, उपेक्षित, सामाजिक वर्ग, कूटयोजना, उत्पीड़न, दण्डकारण्य, अनुक्रिया, वंचना, पुनर्वास।

प्रस्तावना

भारत में अतिवाद को मोटे तौर पर दो भागों में बाँटा गया है–
पहला– आतंकवाद
दूसरा– नक्सलवाद

दोनो समस्याएँ एक दूसरे से बिलकुल विपरीत हैं समानता है तो केवल एक कि दोनो विदेशी सहायता से फलफूल रहे है। भारत का नक्सलवाद यद्यपि भारतीय है किन्तु उसे चीन और नेपाल से सहायता व शस्त्र प्राप्त हो रहे है।

नक्सलवाद या माओवाद वामपंथी अतिवाद का ही नाम है जो भारतीय कम्युनिस्ट आन्दोलन के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ। नक्सल शब्द की उत्पत्ति 1967 में पश्चिम बंगाल के छोटे से गाँव नक्सलबाड़ी से हुई फसल लूट की एक घटना ने भूमिहीन किसानो व भू–स्वामियों के मध्य संघर्ष को जन्म दिया जिसके फलस्वरूप भू–स्वामियों के विरूद्ध भूमिहीन किसानों, श्रमिकों व बेरोजगार युवकों ने अपना आन्दोलन आरम्भ किया जिसे सी.पी.एम. सदस्य एवं जिला स्तरीय नेता चारू मजूमदार ने अपना नेतृत्व प्रदान किया साथ ही सी.पी.एम. के कानू सन्याल भी इस आन्दोलन से जुड़ गये। इस आन्दोलन का क्षेत्र नक्सलबाड़ी दिया गया तथा इस क्रान्ति को नाम दिया गया "सर्वहारा की क्रान्ति"।

सर्वहारा की क्रान्ति और सर्वहारा का नारा लगाने वाले नक्सली आन्दोलन के तीन मुख्य व घोषित उद्देश्य थे –
पहला, – खेत जोतने वाले को खेतो का हक मिले।
दूसरा – विदेशी पूँजी की ताकत समाप्त की जाये।
तीसरा – वर्ग एवं जाति के विरूद्ध संघर्ष हो।

पृष्ठ भूमि

1969 में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की नवीं कांग्रेस में नक्सलवादी नेता चारू मजूमदार ने घोषणा की कि "चीन का चेयरमैन हमरा चैयरमैन है" और नक्सलवादी आन्दोलन में कम्युनिस्ट क्रान्ति से सबक लेते हुए लेनिनवाद, मार्क्सवाद और माओत्से तुंग की विचारधारा को अपना प्रस्थान बिन्दु माना।

सामन्तवाद को समाप्त करने हेतु साम्यवाद का यह संघर्ष उस समय उग्र हुआ जब भूमिहीन किसान एवं उपेक्षित सामाजिक वर्ग ने इसका दामन थाम लिया, भारी भूल, भटकाव तथा राज्य प्रशासन के दमन, दबाव एवं उत्पीड़न के बावजूद नक्सलवाद अपने मूल स्थान पश्चिम बंगाल में तो बहुत अधिक पनप नहीं सका, किन्तु जहाँ नक्सलियों के छिपने एवं कूटयोजना बनाने हेतु जंगल एवं घाटी क्षेत्र विशेष रूप से उपलब्ध है वहाँ अधिक पनपा।

गृहमंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार देश के 14 राज्यों में 160 जिले नक्सली हिंसा से पूरी तरह ग्रस्त हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर लग–भग के

दण्डकारण्य क्षेत्र में नक्सली अपने द्वारा गठित समानान्तर सरकार को जन तन सरकार के नाम से सम्बोधित करते हैं। जनतन सरकार आदिवासियों की आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक स्थिति को सुधारने का कार्य कर रही है। जल, जंगल एवं जमीन पर स्थानीय लोगों के हक के दर्शन से संचालित हो रही है। सबसे ज्यादा नक्सली हमले की छत्तीसगढ़ में ही होते हैं।

नक्सली हिंसा में प्रमुख गुट पीपुल्स वार ग्रुप है जिसे 1980 में सी.पी.आई. (एम.एल.) के विद्रोही नेता कोड़ापल्ली सीतारमैया ने स्थापित किया। 1999 में सी.पी. आई. (एम.एल.) का पार्टी यूनिटी के साथ विलय के बाद से यह संगठन खुद को पीपुल्स वार ग्रुप कहने लगा।

सामाजिक जागृति के लिए शुरू हुए इस आन्दोलन पर कुछ सालों के बाद राजनीति का वर्चस्व बढ़ने लगा और आन्दोलन जल्द ही अपने मुद्दों और रास्तों से भटक गया। जब यह बिहार में फैला तो पूरी तरह से अपने मुद्दों से भटका हुआ था। अब यह लड़ाई जमीनों की लड़ाई न रहकर जातीय वर्ग की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। यहाँ से शुरू होता है उच्च वर्ग व मध्यम वर्ग के बीच का उग्र संघर्ष जिससे नक्सल आन्दोलन ने देश में नया रूप धारण किया।

नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए कांग्रेस नेता महेन्द कर्मा ने 2005 में 'सलवा जुडुम' आन्दोलन की शुरूआत की। सलवा जुडुम आदिवासी, शब्द है जिसका अर्थ है – "शांति का कारवां"।

इस अभियान में ग्रामीणों की फोर्स तैयार करना था, जो माओवादियों के खिलाफ लड़ सके। ग्रामीण आदिवासियों को हथियार देकर उन्हें स्पेशल पुलिस ऑफिसर बनाया गया तथा 1500 /– से 3000/– रूपये तक भत्ता भी दिया जाता उस वक्त बीजेपी के रमन सिंह मुख्यमंत्री थे उन्होने विरोधी पार्टी की सरकार होते हुए भी कांग्रेस के इस अभियान को अपनाया लेकिन मानवाधिकार कार्यकर्त्ताओं के विरोध कि मासूम गाँव वालों को नक्सलियों से सरकार लड़वा रही है पर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँचा और 2011 में इसे अवैध घोषित कर दिया गया। 25 मई 2013 में महेन्द्र कर्मा की महिला नक्सलियों ने कूर हत्या कर दी। 2010 में नक्सलवादी आन्दोलन के प्रणेता कानू सन्याल की आत्महत्या के बाद से नक्सलवादी आन्दोलन की हिंसक घटनाओं में निरन्तर कमी होती जा रही है जिसका कारण सुरक्षा बलों द्वारा संचालित कार्यवाही अभियानों तथा गृह मंत्रालय द्वारा किए गए क्षमता निर्माण के उपायों की कुशलता को प्रदर्शित करते है। भारत सरकार द्वारा अपनाई गई विकासात्मक पहुँच से भारी संख्या में वामपंथियों का हिंसा के मार्ग को छोड़कर मुख्यधारा में वापस लौटते हुए देखा गया है।

भारत में प्रतिबंधित सी.पी.आई. (माओवादी) संगठन दुनिया का चौथा सबसे बड़ा संगठन करार दिया गया है तीन अन्य–तालिबान, आई.एस.आई. और बोकोहरम है।

नक्सली देश की आन्तरिक सुरक्षा एवं राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा बनी हुई है। नक्सली संगठनों ने अपने लड़ाकू दस्तों का सैन्यीकरण करने पर विशेष जोर दिया है व मार्ग से भटके युवाओं को अपने दस्तों में शामिल कर रहे हैं।

नक्सलियों का मुख्य हथियार है जंगलों से उनकी वाकफियत, स्थानीय आदिवासियों से घुल–मिल जाना और घात लगाने की क्षमता। जनता से अलगाव के चलते जवानो को गुप्तचर सूचनाएँ नहीं मिल पा रही हैं। वे न तो स्थानीय भाषा जानते है और न ही संस्कृति। नक्सलियों के मुकाबले सुरक्षाबलों के हथियार व संसाधन बहुत पिछड़े हुए है।

केन्द्र सरकार नक्सली हिंसा को कानून व्यवस्था की समस्या नही मानती इसे सामाजिक आर्थिक समस्या के रूप में सुलझाने की जरूरत समझती है। जब तक आर्थिक विषमताएं समाप्त नहीं होती तब तक नक्सलवादी आन्तरिक अस्थिरता व अशांति पैदा करते रहेंगे। देश के निर्धनतम लोग नेपाल से सटे बिहार की सीमा से लेकर आन्ध्रप्रदेश के रायल सीमा तक की नक्सलवाद प्रभावित पट्टी में संकेन्द्रित है जब तक उनकी शिकायतों का त्वरित निपटान नहीं हो जाता उनका असंतोष और आक्रोश नक्सलवादियों को ऊर्जा प्रदान करता रहेगा।

नक्सलवादियों को भारतीय जनता के केवल एक वर्ग का ही नहीं वरन् समस्त वर्गो का सहयोग मिल रहा है जिसके कारण ही इनका 1500 करोड़ रूपयों का साम्राज्य खड़ा हो सका है तथा नोटबंदी जैसी योजनाएँ भी असफल हो गयी। नक्सलवाद वहाँ ज्यादा पनप रहा है, जहाँ जनजातीय लोग रहते हैं।

नक्सलवाद प्रभावित राज्यों की समस्या के सम्बन्ध से केन्द्र द्वारा बुलाई गई अनेक बैठकों में यह बात सामने आई है कि नक्सली आन्दोलन के खिलाफ चलाये गए अभियानों के दौरान प्रायः केन्द्र राज्य खुफिया ऐजेसियो के बीच समन्वय की कमी पायी जाती हे जिससे अभियानो पर बुरा असर पड़ता है।

नक्सली समस्या के समाधान के दो स्तम्भ बताये गये है –

पहला – सुरक्षा बलों व पुलिस की अनुक्रिया सुनिश्चित करना।

दूसरा – वंचना व अलगाव के बोध को कम करना।

यह सर्वविदित विडम्बना है कि पाँच दशकों से भी अधिक समय से चली आ रही इस समस्या को जड़ से उखाड़ फैंकते का सार्थक प्रयास अभी तक नहीं किया गया है जिससे यह चुनौति अभी भी मुँह बाये खड़ी है। जिन कारणों से नक्सलवाद को बढ़ावा मिला। दुर्भाग्य से वे सभी आज भी मौजूद है, गरीबी, बेरोजगारी व समाज में व्याप्त वर्ग भेद प्रमुख कारण है। भूमि सुधार कार्यकमों पर ईमानदारी से अमल नहीं किया गया। आज भी आदिवासियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है। नक्सलवाद फैल रहा है क्योंकि समाज में असन्तोष व विषमता के कारण बाकायदा बने हुए हैं।

इस क्षेत्र में पायी जाने वाली वन खनिज सम्पदा से आदिवासियों को बेदखल कर पूँजीपतियों, उद्योगपतियों व राजनेताओं ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया साथ ही इन उद्योगों की स्थापना से बड़ी संख्या में आदिवासी विस्थापित हुए जिन्हे उनकी जमीन का ना तो उचित मूल्य और ना ही मुआवजा मिला। जब तक भूख, उत्पीड़न,

दबाव, दहशत, पीड़ा रोजगार वंचित आबादी रहेगी तब तक असंतोष और अराजकता ऐसे आन्दोलनों को जनम देती रहेगी।

जहाँ तक नक्सलवादी गुटों की प्रकृति का प्रश्न है, तो न तो वे अलगाववादी है न ही आतंकवादी और ना ही उन्हें सही रूप में उग्रवादियों की श्रेणी में रखा जा सकता है। उनका विश्वास अवश्य ही लोकतांत्रिक व्यवस्था में नहीं है, घोषित तौर पर वे क्रान्ति करने निकले हैं लेकिन वे स्वयं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते कि कुछ निर्दोष लोगों की हत्या करके वे लोग कौन सी क्रान्ति कर लेंगे। नक्सलियों की नजर में उनका वह हर व्यक्ति दुश्मन है जो वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखते है।

सुझाव

इस समस्या को निपटाने के उपायों पर विचार किया जाय तो निम्नलिखित सुझाव निकल कर सामने आते है–

1. आमधारा से विपरीत नक्सलियों को सदी दशा–दिशा मिले इसके लिए सरकार को नक्सलियों से आमने–सामने की बातचीत की पहल करनी होगी इसके लिए पहले उन्हें हथियार समर्पण के लिए तैयार करना होगा।
2. नक्सली एवं गैर–नक्सली की पहचान अत्यन्त आवश्यक है।
3. आदिवासियों के लिए शिक्षा, रोजगार व पुनर्वास के तीव्र प्रयास करने होंगें।
4. संवेदनशील क्षेत्रों में भ्रष्टाचार मुक्त व संवेदनशील राजनीतिक व प्रशासनिक नेतृत्व प्रदान किया जाये।
5. नक्सलियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियानो में केन्द्रीय बलों खुफिया ऐजेन्सियों और स्थानीय बलों के बीच बेहतर तालमेल का अभाव दिखाई देता है इसे दुरूस्त किया जाए।
6. जम्मू कश्मीर की तरह नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में भी एकीकृत कमान का गठन किया जाये। खुफिया तन्त्र को इस तरह से प्रशिक्षित किया जाये कि वे ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर सके व स्थानीय जनता से नक्सलियों के दिन–प्रतिदिन की गतिविधियों की सूचना एकत्रित कर सकें।
7. पुलिस और अर्द्धसैनिक बलो की आधुनिक हथियार में आवागमन के संसाधन उपलब्ध करवाये जायें। साथ ही नक्सलियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियानो को सफल बनाने के लिए वायु सेना का उपयोग भी सीमित रूप से किया जाए।

निष्कर्ष

वस्तुतः समस्या का खात्मा करने के लिए समस्या की जड़ को खत्म करना चाहिए जिसमें सरकार असफल रही है विकास व खनन कार्यों के नाम पर जनजातियों को बेदखल करना व पुनर्वास की समुचित व्यवस्था ना करना सरकारी तंत्र का भ्रष्टाचार जिसमें इनकी सुनवाई नहीं हो रही असंतोष का एक बड़ा कारण है। ये समस्या सेना या अर्दसैनिक बलों की तैनाती से नहीं दूर होगी बल्कि उन्हें मूलभूत सुविधाएँ शिक्षा तथा रोजगार देकर युवाओं को भटकाव के मार्ग पर जाने से रोकने पर होगी।

प्रशासन को पारदर्शी व संवेदनशील होना होगा और स्थानीय लोगो के साथ तालमेल बिठाकर समस्याओं के त्वरित समाधान करना होगा।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. *Ramkrishnan Venkitesh (12 September, 2005): The Naxalite Challenge, Front line Magazine.*
2. *Sen, Sunil Kumar (1982) Peasant Movements in India: Mid-Nineteenth and Twentieth Centuries Calcutta : KP Bagchi*
3. *South Asia : Senior Mauist Arrested in India BBC News 19 Dec., 2007*
4. *Johari J.C. Naxalite Politics in India New Delhi, 1972*
5. *हिन्दुस्तान समाचार पत्र, 25 अप्रैल 2017*
6. *Raghavan V.R. : The Naxal threat : Causes State Responses and Consequences.*
7. *पुखराज जैन : भारतीय राज व्यवस्था*